

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 26/11/2008

विशय:- सेठ विमल प्रसाद जैन, एजुकेशनल ट्रस्ट को तहसील रुडकी के ग्राम इमलीखेडा धर्मपुर जनपद हरिद्वार में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना हेतु कुल 12.50 एकड़ भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-909/भूमि व्यवस्था दिनांक-18.10.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सेठ विमल प्रसाद जैन, एजुकेशनल ट्रस्ट को तहसील रुडकी के ग्राम इमलीखेडा धर्मपुर जनपद हरिद्वार में शैक्षणिक संस्थान जिसमें बी०टेक, एम०बी०ए० तथा एम०सी०ए० पाठ्यक्रम का संचालन किया जाना है, की स्थापना हेतु कुल 12.50 एकड़ भूमि आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा -129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (तकनीकी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि

का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये, विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग तकनीकी शिक्षा संस्थान हेतु कर लिया जायेगा।

8- संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना हेतु नियमानुसार ए0आई0सी0टी0ई0 को आवेदन कर दिया जाएगा जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9- संस्था द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

13- सम्बन्धित इकाई द्वारा उत्तराखण्ड मूल के 70 प्रतिशत बेरोजगारों को निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

14- इकाई द्वारा प्रस्तावित भूमि पर स्थित पेड़ों के कटान के सम्बन्ध में नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

15- स्थापित की जाने वाली इकाई के विनियमित क्षेत्र रुडकी के अन्तर्गत होने की स्थिति यद्यपि स्पष्ट नहीं है तथापि सम्बन्धित संस्था द्वारा परियोजना निर्माण से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से भू-उपयोग के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)  
अपर सचिव।

पृ0प0सं0-1215/समदिनांकित 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- सेठ विमल प्रसाद जैन, एजुकेशनल ट्रस्ट-73 न्यू हरिद्वार रोड सिविल लाइन रुडकी, तहसील रुडकी जनपद हरिद्वार।
- 6- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)  
उप सचिव।